श्री कपिल सिब्बल: सर, अभी भी जो मकेनिज्म चल रहा है, आज के दिन pricing is an impossible thing because you are going to calculate the import price in respect of chemical based fertilizers. Import prices will have to be calculated on a monthly basis because the international prices will move. How are you going to do that? How is the system going to work?

MR. CHAIRMAN: Next question.

Progress under 'Sarva Shiksha Abhiyan'

*90. SHRI MURLI DEORA:
SHRI DRUPAD BORGOHAIN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Ministry's flagship programme 'Sarva Shiksha Abhiyan' has achieved any amount of success;

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of the States which are not taking keen interest in the programme and not releasing funds of their share;

(d) the amount granted to each State for 2002-03 and the amount spent by them so far;

(e) whether there is any common standard prescribed to build schools and to supply different materials to the schools in a State; and

(f) how are the propagators of 'Sarva Shiksha Abhiyan' appointed and what is their individual emolument?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SANJAY PASWAN): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) The Government has launched the programme of *Sarva Shiksha Abhiyan* in November. 2000 to achieve the goal of Universalisation of Elementary Education in Mission mode in partnership with States. Out of the 600 districts in the country, District Elementary

Education Plans (DEEPs) of 592 districts were apporoved at an outlay Rs. 3080.10 crores during 2002-03.

During 2003-04 DEEPs of 422 districts from 15 States and 2 Union Territories at an outlay of Rs. 5944.16 crores have been approved so far. DEEPs have been received from all other States/Union Territories except Goa and these are being appraised before consideration by the Project Approval Board. Only three States and one Union Territory, namely, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, and Lakshadweep had not released State share to their respective State Implementing Societies.

(d) A Statement showing State-wise grants released and expenditure incurred under SSA during 2002-03 is enclosed (*See* below).

(e) The programme envisages provision of two classrooms with a verandah to every Primary School; a room for every grade/class and a room for the Head Master in Upper Primary School. The participation of community in all civil work activities is mandatory in order to ensure a sense of ownership and use of local construction material and low cost. technology is being promoted.

(f) There is no provision for appointment of propagators under *Sarva Shiksha Abhiyan.*

Statement

Regarding progress under Sarva Shiksha Abhiyan

(Rupees in lakhs)

Sl. No.	Name of the State/UT	Grants released (SSA) 2002-03 by GoI	Expenditure incurred during 2002-03
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	8226.1	3952.34
2.	Assam	10175.92	5197.82
3.	Arunachal Pradesh	1412	0
4.	Bihar	7914.97	7492.65
5.	Chhattisgarh	3639.73	2413.6

1 2	3	4
6. Gujarat	14004.3	9287.02
7. Himachal Pradesh	1717.62	1911.95
8. Haryana	2735.87	2613.47
9. Jharkhand	3244.32	2231.85
10. J&K	1948.85	1448.5
11. Kerala	2250.78	3122
12. Karnataka	8270.46	7096
13. Madhya Pradesh	11017.1	1081.86
14. Meghalaya	711.37	955.18
15. Mizoram	903.29	432.56
16. Maharashtra	11000	9671.41
17. Nagaland	973.28	N.A.
18. Orissa	2214.15	1205.32
19. Punjab	4868	11444.77
20. Rajasthan	9995.58	4522.01
21. Sikkim	425.14	309.02
22. Tamil Nadu	13526.9	10570.53
23. Tripura	1162.18	495.72
24. Uttar Pradesh	20245.4	6402.88
25. Uttaranchal	2067.69	1855.82
26. West Bengal	10867.61	8811.87
27. Daman & Diu	12	N.A.

1 2	3	4
28. Delhi	161.27	52.22
29. Lakshadweep	19.98	N.A.
30. Pondicherry	116.46	0
TOTAL:	155828.32	114298.37

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, my first supplementary is, it is known in Assam that some LP schools get Rs. 7,000 only from the *Sarva Shiksha Abhiyan* fund for development. What will they do with this meagre money because they cannot build even a *baramda* or a headmaster's room with this money. I would like to know from the Minister: Is it not wastage of money? How can it be properly utilized? Will it not create hurdles in achieving the real purpose of *Sarva Shiksha Abhiyan?*

डा॰ संजय पासवान: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को बधाई दूंगा कि उन्होंने कहा है कि यह मंत्रालय की फ्लेगशिप स्कीम है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इसके कई कंपोनेंट हैं। एक तो जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं और ऐसा क्षेत्र जहां स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल बनाना है। इसलिए कई कंपोनेंट इसके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह ओवर ऑल है, स्कूल बिल्डिंग बनाने के अलावा टीचर्स का जो लिटरेसी मेटीरियल वगैरह जो है उसके अलावा वह सात हजार रुपया खर्च कर सकता है। इसलिए उसके लिए कई कंपोनेंट बने हुए हैं। आसाम के संबंध में मैंने विशेष तौर से उनसे कह दिया है और अगर वे चाहेंगे तो मैं अलग से दे सकता हूं। लेकिन वह सात हजार विशेष रूप से दिया गया है जो उनकी मरजी पर है तथा जिसका विशेषाधिकार है शिक्षक को। केवल उतनी ही राशि देकर खत्म नहीं कर दिया गया है। उसके कई फंड हैं, उसके कई कंपोनेंट हैं जिसमें एक में सात हजार की राशि दी गई है।

SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Sir, my second supplementary is that I have seen there that some teachers are moving from one school to the other school in the name of training or something else under the *Sarva Shiksha Abhiyan*. I want to know whether the first school, where he or she has taught, would not suffer if the teacher is moved in this manner.

डा॰ संजय पासवान: ट्रांसफर तो ऐडमिनिस्ट्रेशन का एक जनरल अफेयर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग कंपोनेंट के लिए जितनी बड़ी राशि इसमें मुहैया की गयी है और ट्रेनिंग के लिए वे कहीं जाते हैं तो उससे इस स्कीम का असर भी पड़ने वाला है। जो रिपोर्ट्स स्टेट्स से आ रही

हैं, वे बड़ी उत्साहवर्धक हैं। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 2003 तक निश्चित तौर से हम सब लोग किसी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं देख पाएंगे। सारे बच्चे स्कूल में रहेंगे, उनका एनरोलमेंट होगा। ऐसी रिपोर्ट्स स्कूलों से आ रही हैं और उनके आधार पर ऐसा मेरा विश्वास है।

SHRI EDUARDO FALEIRO: In reply to my Special Mention, the hon. Minister had admitted that the funds for this *Sarva Shiksha Abhiyan* are not sufficient, and that the Minister would be approaching the Finance Ministry and the Planning Commission to get additional funds. Now, my question is: Have you got any additional funds? If not, how do you intend to implement the scheme? And, are you bringing in the Bill in this Session for universalisation and compulsory elementary education?

डॉ॰ संजय पासवान: सभापति महोदय, जो टास्क फोर्स बनायी गयी थी, उसने 32 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, उसके मुताबिक अभी तक हमें इस प्लान में 17 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। इस प्लान में राज्यों को जो राशि मिल रही है, अभी वह राशि भी पूरे तौर पर खर्च नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है, हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने प्लानिंग कमीशन को लिखा है, वित्त मंत्री जी को भी लिखा है और प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है। चूंकि प्रधान मंत्री इसके चेयरमैन हैं, इसलिए फंड की कमी इस स्कीम के लिए कहीं से नहीं आने वाली है, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जो फंड राज्यों को गया है, उसका भी पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हम माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि उनके राज्यों में उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल हो और उसका अनुसरण ठीक ढंग से हो, इस बात को सुनिश्चित करें। फंड की कमी इस स्कीम में नहीं आने वाली है।

SHRI EDUARDO FALEIRO: What about the Bill? I had asked whether you are bringing the Bill in this Session.

DR. SANJAY PASWAN: It is in the process.

MR. CHAIRMAN: This is not within the scope of this question.

प्रो॰ रामगोपाल यादव: महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री ने कुछ समय पहले संसद सदस्यों को एक पत्र लिखा था, एलीमेंटरी ऐजूकेशन से संबंधित सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए वे लोग भी, जहां स्कूल भवन नहीं हैं, वहां बनवाने के लिए एमपीलैड्स से धन दें। मैंने उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में लगभग 60 प्राइमरी स्कूलों के भवन बनवाकर दिए। लेकिन बगल में ही एक मैनपुरी जनपद है, वहां स्कूल बनवाने के लिए जब मैंने पैसा भेजा तो जिला प्रशासन ने यह कहकर मना कर दिया कि इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुमति नहीं दे रहा है। एक तरफ केन्द्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय संसद सदस्यों को रिक्वैस्ट करता है कि एमपीलैड्स से जहां स्कूल नहीं हैं, वहां स्कूल बनवाने के लिए, प्राइमरी ऐजूकेशन के लिए धन दिया

जाये और दूसरी तरफ कुछ जनपद ऐसे हैं जहां अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या अगर इस बात को हम लिखकर दें तो आप इस बात की जांच कराएंगे और संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इसमें कोई विघ्न न डालें, कोई बाधा न डालें।

डा॰ संजय पासवान: इस संबंध में पूरे तौर से राज्यों ने अपनी-अपनी व्यवस्था कर ली है और विभिन्न राज्यों में अथॉरिटी के माध्यम से या मिशन के माध्यम से यह स्कीम चल रही है। जिला स्तर पर भी अलग से जिला शिक्षा अधिकारी या उसके अतिरिक्त एक अधिकारी को इस काम के लिए चिन्हित किया गया है। जहां तक यह मामला है, यह मामला जिला और स्टेट की राजधानी का मामला है। अगर हमारे संज्ञान में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर हम इस पर ऐक्शन लेंगे और चाहेंगे कि इसमें कोई बाधा न हो और माननीय सदस्य अगर उसमें मदद करना चाह रहे हैं तो यह अच्छी बात है और इस स्कीम के प्रति उनकी स्वीकृति है, ऐनडोर्समेंट है और उनकी रुचि इस स्कीम में बढ़ रही है। अगर हम लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा तो हम लोग उस पर जरूर ऐक्शन लेंगे।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, हमें भी सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत दी जाए।

श्री सभापति: आपने 96 के लिए दिया था। प्रश्न संख्या 91।

Rail accidents

*91. PROF. SAIF-UD-DINSOZ:
SHRI MANOJ BHATTACHARYA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the details of accidents during the past three years, date-wise,

(b) the number of deaths in these accidents;

(c) the cumulative amount of *ex-gratia* payments made by Government to the next of kin of the deceased and the injured;

(d) whether the broad reasons for such frequent railway accidents have been identified;

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(f) steps proposed to be taken to prevent the accident and make railway journey safe for the passengers?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Sabha.